



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ६, अंक २९]

बुधवार, ऑक्टोबर २८, २०२०/कार्तिक ६, शके १९४२

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४१

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकार्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२०

क्रमांक जीवका. १५२०/प्र.क्र. ४३/नापु २३.—भारत सरकार, ग्राहक बाबी, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (ग्राहक बाबी विभाग) नवी दिल्ली यांच्याकडून असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उप खंड (ii) मध्ये दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे :—

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, २३ अक्टूबर, २०२०

आदेश

का.आ. ३७७६ (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, २०१६ का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम और लागू होना.— (१) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, २०२० है।

(२) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

२. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, २०१६ में खण्ड ३ के उप-खण्ड (२) में, मद संख्या (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(iv) प्याज के मामले में, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में व्यापारियों पर दिनांक ३१ दिसंबर २०२० की अवधि तक निम्नलिखित स्टॉक सीमा ;

थोक विक्रेता : २५ मीट्रिक टन एवं खुदरा विक्रेता: २ मीट्रिक टन

बशर्ते कि आयातक, जो थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता अथवा डीलर है, को प्याज के आयातित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी।”

[फा.सं.एस-१०/३/२०१७-ई सी आर एंड ई]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 23rd October 2020

Order

S.O.3776 (E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby, makes the following order further to amend the removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely :—

1. *Short Title and Commencement*— (1) This Order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), after the item (iii), the following item shall be inserted namely :—

“(iv) Onion, for a period upto the 31st December 2020 with following stock limits on traders for all the States and Union Territories ;

Wholesaler : 25 MT and Retailer : 2 MT

Provided that an importer, being a wholesaler or retailer or dealer shall be exempted for the imported stock of onions.”

[F.No. S-10/3/2017-ECR&E]

ANUPAM MISHRA,

Joint Secretary.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

चारूशीला तांबेकर,

शासनाच्या सहसचिव.